श्रीराम अस्पताल में ड्रग कंट्रोलर का छापा, डिस्पेंसरी बंद

मजदूर मोर्चा ने इस अस्पताल में एक्सपायरी दवा बेचे जाने की खबर पिछले अंक में छापी थी

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: श्रीराम धर्मार्थ अस्पताल में ड्रग कंट्रोलर की टीम में पिछले सोमवार (9 अगस्त) को छापा मारा। श्रीराम धर्मार्थ अस्पताल में एक्सपायरी तारीख की दवाई बेचे जाने की खबर मजदूर मोर्चा ने 8 अगस्त को छापी थी। इसके बाद 9 अगस्त को ड्रग कंट्रोलर कर्ण सिंह गोदारा और पूजा शर्मा तिकोना पार्क स्थित श्रीराम धर्मार्थ अस्पताल में पहुंचे और दवाइयों की जांच शुरू कर दी। लेकिन अस्पताल को जबरन संचालित कर रहे लोगों को इसकी भनक मिल गई या वो खबर छपने के बाद अलर्ट हो गए, जब ड्रग कंट्रोलर की टीम वहां पहुंची तो उसे कोई दवाई अस्पताल की डिस्पेंसरी में नहीं मिली।

ड्रग कंट्रोलर कर्ण गोदारा ने मजदूर मोर्चा को बताया कि हमने अस्पताल की डिस्पेंसरी के अलावा अस्पताल का कोना-कोना छान मारा लेकिन हमें कहीं कोई दवा वहां नहीं मिली। गोदारा ने बताया कि अस्पताल में चल रही डिस्पेंसरी का लाइसेंस जल्द ही खत्म होने वाला है। इस संबंध में श्रीराम धर्मार्थ अस्पताल को चेतावनी दी गई है कि वे अपना लाइसेंस का जल्द से जल्द नवीनीकरण करा लें। हालांकि कर्ण गोदारा ने यह नहीं बताया कि श्रीराम अस्पताल में किस बी. फार्मा लाइसेंस वाले की आड़ लेकर जो डिस्पेंसरी चलाई जा रही है, वहां मौके पर वह केमिस्ट या लाइसेंस होल्डर मौजूद था या नहीं। गोदारा ने कहा कि अगर किसी ने इस अस्पताल से एक्सपायरी दवाई खरीदी है और उसके पास पर्ची है तो उनके पास जमा करा सकता है, उस स्थिति में इस अस्पताल की डिस्पेंसरी पर कार्रवाई की जाएगी। गोदारा ने आशंका जताई कि चूंकि यह अस्पताल लंबे समय से बंद था, तो हो सकता है वहां पुरानी दवाइयां पड़ी रही हों। उन्होंने कहा कि हमारी नजर इस अस्पताल पर बराबर बनी हुई है।

बता दें कि मजदूर मोर्चा के पिछले अंक में अवैध रूप से चलाए जा रहे श्रीराम अस्पताल से एक्सपायरी डेट की दवा बेचे जाने की खबर छापी थी। अस्पताल ने किसी बी. फार्मा वाले के लाइसेंस की आड़ में यहां डिस्पेंसरी खोल रखी थी। लेकिन सोमवार को यहां छापा पड़ा और उसी दौरान सारी दवाइयां डिस्पेंसरी से हटा दी गईं। अस्पताल का कथित मैनेजमेंट देख रहे निलम्बित प्रधान कंवल खत्री और उनके दायें-बायें हाथ जोगिन्द्र चावला ने अब वहां बैनर टांग दिया है कि डिस्पेंसरी बंद है।

इतनी फजीहत के बाद भी अवैध रूप से चलाए जा रहे इस अस्पताल की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए कंवल खत्री गुट राजी नहीं है। श्रीराम चेरिटेबल सोसाइटी की एफडी में से 11 लाख रुपये खर्च करने यानी उड़ाने के बाद भी अस्पताल की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पा रही हैं।

प्रशासक को अब वेतन क्यों

श्रीराम धर्मार्थ सोसाइटी में विवाद होने पर जिला रजिस्ट्रार सोसाइटीज फरीदाबाद ने यहां संत गोपाल नामक शख्स को तीन महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किया था। इस प्रशासक का कार्यकाल 8 मई को ही खत्म हो चुका है। उसका कार्यकाल बढ़ाने या नया प्रशासक नियुक्त करने की सूचना न तो श्रीराम धर्मार्थ सोसाइटी के पास पहुंची और न ही जिला रजिस्ट्रार दफ्तर में ऐसी सूचना पहुंची। लेकिन कंवल खत्री गुट ने प्रशासक को अभी भी पद पर मानते हुए संत गोपाल को 21000 हजार रुपये वेतन 28 जुलाई को दिया है। इसके लिए सोसाइटी के खाते से पैसा निकलवाया गया है। संत गोपाल ने वह वेतन ले भी लिया, लेकिन उस शख्स के पास किसी भी तरह का उसका कार्यकाल बढ़ाए जाने की सूचना नहीं है। गढ़वाल सभा की सोसाइटी में भी यह शख्स प्रशासक है, वहां जाकर वेतन लेने वाले लंच में मटर पनीर मांगने वाले इस कथित प्रशासक पर कंवल खत्री गुट इसलिए मेहरबान है, क्योंकि अस्पताल में घुसने का रास्ता इसी प्रशासक ने दिखाया था। इसलिए कंवल खत्री गुट अब सोसाइटी के पैसे से इसे वेतन देकर कृतार्थ कर रहे हैं।

संत गोपाल को तीन महीने के लिए प्रशासक बनाया था। लेकिन इसी बीच यह मामला जिला ग्रीवेन्स कमेटी में पहुंच गया था। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में 28 जून को हुई इस बैठक में आदेश दिया गया था कि एक नई कमेटी सारे मामले की जांच करेगी। तब तक सारी व्यवस्था एसडीएम की देखरेख में होगी। यानी 28 जून के फैसले के बाद वैसे भी इस प्रशासक का कोई महत्व नहीं रह गया था। लेकिन कंवल खत्री ने ग्रीवेन्स कमेटी में दिए गए निर्देशों की अनदेखी करते हुए कथित प्रशासक को वेतन देना जारी रखा हुआ है।

17 अगस्त को जांच

इस बीच जिला ग्रीवेन्स कमेटी में लिए गए निर्णय के आधार पर इसकी जांच अब नगर निगम फरीदाबाद के साफ सुथरी छवि वाले चीफ टाउन प्लानर धर्मपाल को सौंपी गई है। उन्होंने 17 अगस्त को निलम्बित प्रधान कंवल खत्री और सोसाइटी के उप प्रधान विशाल भाटिया को अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। चीफ टाउन प्लानर सारी स्थिति जानने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेंगे। यह रिपोर्ट आगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला तक भी समीक्षा के लिए भेजी जाएगी। ऐसे में एमसीएफ के सीटीपी तटस्थ रहकर ही कोई फैसला करना चाहेंगे।

इस बीच श्रीराम धर्मार्थ अस्पताल के संस्थापक सदस्य एस.एम. हाशमी ने कहा है कि निलम्बित प्रधान कंवल खत्री एंड कंपनी ने उनके नाम पर ट्रांस एशिया के बिल में पैसों की जो धोखाधड़ी की है, जिला प्रशासन और जांच करने वालों को उसका खुद से संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि यह 420 का मामला है। एक तरफ तो सोसाइटी उन्हें अपना सदस्य तक नहीं मान रही, न बैठकों में बुलाती है। ऐसे में ट्रांसएशिया कंपनी को जो लाखों का बिल भुगतान किया गया है, उसके संपर्क व्यक्ति के रूप में बिल में उनका नाम किस तरह आया है। यह एक तरह से उनकी मानहानि है। अगर इस संबंध में सोसाइटी और कंवल खत्री गुट अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करते हैं तो उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा।

देखी-सुनी

खबरीलाल

सरकार की औक़ात पता चल गई

इस बार स्वतंत्रता दिवस हरियाणा की खट्टर सरकार पर भारी पड़ गया है। उसके कई मंत्री जो 15 अगस्त पर झंडा फहराने की तैयारी कर रहे थे, उनके चेहरों पर मायूसी छा गई है। दरअसल, हरियाणा के ग्रामीण इलाक़ों में किसानों के ज़बरदस्त विरोध के कारण खट्टर सरकार के मंत्री तमाम ज़िलों में झंडा फहराने के लिए जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में विभिन्न ज़िलों में झंडा फहराने का जो कार्यक्रम घोषित किया है, उसके मुताबिक़ कैथल, रोहतक, सिरसा, कुरुक्षेत्र, जीन्द, झज्झर और सोनीपत ज़िले में वहाँ के डीसी झंडा फहराएँगे। इन सात शहरों में कोई मंत्री झंडा फहराने नहीं जाएगा। खुद मुख्यमंत्री फ़रीदाबाद और राज्यपाल गुड़गाँव में झंडा फहराएँगे। जिन सात शहरों में खट्टर के मंत्री झंडा फहराने नहीं जा पा रहे हैं, वे पूरी तरह किसान बेल्ट के इलाक़े हैं और जहां किसान आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। मात्र इस एक घटनाक्रम से खट्टर सरकार और तिरंगा यात्रा निकाल रही भाजपा को अपनी औक़ात पता चल गई है कि वह हक़ीक़त में कहाँ खड़ी है। यहाँ पर क्या यह याद दिलाने की ज़रूरत है कि सीएम खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ जीन्द के गाँवों में क्या क्या नहीं हुआ। हैलीपैड खोदने से लेकर मंच तोड़ने और हेलिकॉप्टर न उतरने देने की घटनाएँ ज़्यादा पुरानी नहीं हैं।

15 अगस्त को फ़रीदाबाद वाले घरों में रहें

फ़रीदाबाद में इस बार स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में आम जनता शायद ही शिरकत कर पाये। पूरे ज़िले में धारा 144 लगा दी गई है। ऐसा सीएम मनोहर लाल खट्टर की वजह से हो रहा है। वह 15 अगस्त को झंडा फहराने आ रहे हैं। उनकी सुरक्षा के नाम पर धारा 144 लगा दी गई है ताकि गाँवों से अगर जो लोग विरोध करने के लिए फ़रीदाबाद आना चाह रहे हैं तो वो नहीं आ सकें। जबकि आज़ादी के जश्न का संबंध सीधा जनता से है। लेकिन अब ऐसी सरकार सत्ता में आई है जो चाहती है कि आम लोग आज़ादी के जश्न में शामिल ही नहीं हो सकें। आमतौर पर स्वतंत्रता दिवस पर धारा 144 लगाने का चलन नहीं रहा है लेकिन यह सरकार जो न कराए थोड़ा है। यहाँ पर एक घटना का ज़िक्र सरकार को याद दिलाने के लिए है। जब पूर्व राज्यपाल तपासे ने बेईमानी से भजनलाल की सरकार हरियाणा में बनवा दी थी तो जीन्द का एक जाट फ़रीदाबाद आया और स्वतंत्रता दिवस पर वाईएमसीए में होने वाले समारोह में शामिल हुआ। तपासे ने भाषण ख़त्म किया, उस युवक ने तपासे के चेहरे पर कालिख मल दी। वह निहत्था था, सिर्फ़ काली स्याही थी। वह चौधरी देवीलाल का अनुयायी था। ...तो डीसी फ़रीदाबाद यह जान लें कि विरोध पर कोई आमादा होगा तो सरकार की पुलिस उसे रोक नहीं पाएगी।

एमसीएफ में हर मर्ज़ की दवा है जाँच

नगर निगम फ़रीदाबाद (एमसीएफ) भ्रष्टाचार का अड्डा तो बना ही हुआ है लेकिन अब यहाँ हर काम को, हर मामले को जाँच की आड़ में टाला जा रहा है। एमसीएफ के एसडीओ जीतराम ने अपने मुँहलगे जेई योगेश से कहकर एनआई नंबर 1 में एफ और के ब्लॉक में दो बिल्डिंगों को सील करा दिया। बिल्डिंग मालिक अपनी फ़रियाद लेकर एमसीएफ पहुँचे तो वहाँ कमिश्नर के नहीं मिलने पर फ़रियाद ज्वाइंट कमिश्नर प्रशांत अटकान के पास जा पहुँचे। बिल्डिंग मालिकों ने अटकान से कहा कि उनकी सीएएलयू फ़ीस और इम्पाउंड फ़ीस जमा है। फिर भी बिल्डिंग सील कर दी गई। ज्वाइंट कमिश्नर अटकान ने उनके दस्तावेज़ों की जाँच के बाद कहा कि एसडीओ और जेई को सील करने का अधिकार नहीं है। इसके बाद फ़रियादी कमिश्नर यशपाल यादव के पास पहुँचे और कहा कि अगर सील न खुली तो वे खुदकुशी कर लेंगे। इस बीच ज्वाइंट कमिश्नर ने भी एसडीओ और जेई की शिकायत कमिश्नर यादव से कर दी। पिछले मामलों की तरह कमिश्नर ने इसकी जाँच का आदेश दे दिया और मामले को निपटा हुआ मान लिया। दूसरी तरफ़ एसडीए ने शहर में चर्चा का बाज़ार गर्म करा दिया कि इस मामले में ज्वाइंट कमिश्नर प्रशांत अटकान क्यों रूचि ले रहे हैं। इस तरह मूल मुद्दा दब गया और सारी कहानी ज्वाइंट कमिश्नर बनाम एसडीओ हो गई। कमिश्नर यादव की जाँच से तो कुछ न हो पाएगा लेकिन शहर में जनता को संदेश जा रहा है कि एमसीएफ में किसी एक अफ़सर का पेट भरने से सभी के पेट भरना नहीं मान लेना चाहिए।

मझावली यमुना पुल : इन्तजार की 7वीं वर्षगांठ

फ़रीदाबाद (म.मो.) 14 अगस्त 2014 को बड़ी धूम-धाम से केन्द्रीय सड़क मंत्री नितिन गटकरी व स्थानीय सांसद कृष्णपाल गूजर ने नोएडा को जोड़ने वाले इस पुल की आधारशिला रखी थी। इस अवसर पर ज़िले भर से लाखों लोग़ों को ट्रालियों, ट्रकों व बसों में ढोकर लाया गया था। दावा किया गया था कि दो साल में पुल चालू हो जायेगा। **'मज़दूर मोर्चा'** ने उसी वक्त घोषित कर दिया था कि दो साल में तो यदि डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट) रिपोर्ट बन जाय तो समझो बड़ी बात है, पुल चालू होने की तो छोड़ो। वही हो रहा है। आज पूरे सात वर्ष हो चुके हैं, पुल चालू होने के फ़िलहाल कोई आसार नहीं दिख रहे।

हां, जनता को बहलाये रखने के लिये यदा कदा कृष्णपाल इसे लेकर ऊल-जुलूल बयानबाज़ी जरूर करते रहते थे; कभी पुल को जोड़ने वाली पहुंच सड़क के लिये ज़मीन अधिग्रहण करने की तो कभी वहां भंडारा करने की तो कभी जनता को पुल बन जाने से होने वाले लाभ गिनवाने को प्रेसनोट जारी करते थे। लेकिन अब तो

कई वर्षों से गूजर महोदय ने उसकी चर्चा तक भी करना छोड़ दिया, जाहिर है आखिर कब तक किसी को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है?

सरकार की काहिली का आलम तो यह है कि पुल, यदि बन भी गया तो वहां तक पहुंचने के लिये ढंग की सड़क तक नहीं है, चार गांवों की गलियों से होकर गुजड़ना पड़ता है। ऐसी ही दुर्दशा छांयसा के इलाके में केजीपी हाईवे तक जाने वाली की तो होती ही है साथ भुगतना उन पांच गांव वालों को भी पड़ता है जिनके यहां भारी ट्रैफ़िक का जाम लगा रहता है और वायु प्रदूषण होता है।

मझावली पुल चालू होने के चलते जनता को रोजाना लाखों का तेल फूंक कर दिल्ली का चक्कर काट कर नोएडा जाना पड़ता है। जनता भुगत रही है तो भुगते, भाजपा सरकार की प्राथमिकता पुल बनाना नहीं मंदिर बनाना है, धारा 370 हटाना व हिन्दू-मुस्लिम दंगे करा कर वोट लेना है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06